



2026:AHC:59520

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2374 सन 2026

आलोक मिश्रा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता	:	संतोष कुमार तिवारी
विपक्षीगण के अधिवक्ता	:	जी ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार तिवारी, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री शिव दत्त शुक्ला को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- प्रस्तुत आवेदन वाद अपराध संख्या- 306 सन् 2025 से संबंधित है, जो बी.एन.एस. की धारा 115(2), 352, 351(3), 118(2), थाना पिपीगंज, जनपद गोरखपुर के अधीन पंजीकृत है, जिसमें गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए अग्रिम जमानत का निवेदन किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा उसमें आरोप है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने प्रथम सूचनादाता के पुत्र पर कठोर एवं भोथरी वस्तु तथा ईंटों से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप घायल की आँख पर चोट आई। अन्वेषण के दौरान आवेदक का नाम प्रकाश में आया। घायल को प्राप्त चोटें जीवन के लिए घातक नहीं पाई गई हैं। आगे यह भी निवेदित किया गया कि कथित घटना के पश्चात घायल के नेपाल जाने और वहाँ उसका ऑपरेशन किए जाने का कथन है, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट नौ दिनों की देरी से दर्ज की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा।
- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध नौ दिनों की देरी से दर्ज की गई है, जिसमें यह आरोप है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने प्रथम सूचनादाता पर कठोर एवं भोथरी वस्तु तथा ईंटों से प्रहार किया,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिसके परिणामस्वरूप घायल की आँख पर चोट आई। आगे, अन्वेषण के दौरान आवेदक का नाम प्रकाश में आया।

6. यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से पलायन की संभावना तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, और अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का एक उपयुक्त मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त वाद अपराध में गिरफ्तारी की दशा में, आवेदक- आलोक मिश्रा को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों सहित अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त कराए जाने हेतु उपयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

रमा कान्त

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"